ऊर्जा नियामक बोर्ड सही मत प्राप्त करने के लिए इन मतों और दृष्टिकोणों को ध्यान देता है और अपनी चर्चाओं और विचार-विमर्श में बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करता है।

जनता में पर्यावरणीय जागरूकता लाने के लिए वित्तीय सहायता

3176. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रदूषण के खिलाफ देश में जागरूकता लाने के लिए और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इन संस्थाओं में से प्रत्येक को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) प्रदूषण विरोधी अभियान में लगी संस्थाओं की संख्या कितनी हैं और वित्तीय सहायता के लिए संस्थाओं के चयन का मापदण्ड क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है ;

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संबंधी बदरुद्दीन तैयबजी समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

3177. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में बदरुद्दीन तैयबजी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की योजना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट ने 10-11 अगस्त, 1987 को हुई अपनी बैठक में विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों मे मुस्लिम छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण के संबंध में इसके तीन सदस्यों द्वारा प्रस्तावित अलग-अलग प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि प्रस्ताव से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कुलपति द्वारा बनी सदस्यो की समिति गठित की जाए। कोर्ट के प्रस्ताव अनुसरण में कुलपति ने इस उद्देश्य के लिए नौ सदस्यों की समिति (तैयबजी समिति) नियुक्त की। समिति का विचार था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विशेष स्वरूप को देखते हुए विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति अधिक संख्या में मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देना होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तैयबजी समिति ने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए हैं ;

(i) कक्षा XI, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 50% सीटें सभी समुदायों से संबंधित छात्रों की समेकित सूची में से योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए। शेष 50% सीटें उन मुस्लिम छात्रों को छोड़ते हुए, जिनका चयन समेकित सूची में से कर लिया गया है, केवल मुस्लिम छात्रों की सूची में से योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए।

(ii) कक्षा XI में प्रवेश के लिए योग्यता आवेदक द्वारा अर्हक परीक्षण मे प्राप्त अंकों के आधार पर रखी जाए जबकि सभी विषयों में स्नातक

स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देश के विभिन्न केन्द्रों में आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। डिप्लोमा व डिग्री स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाना चाहिए जो केवल अलीगढ में आयोजित न करके देश के विभिन्न केन्द्रों में आयोजित की जानी चाहिए ।

(iii) विश्वविद्यालय के सामूहिक जीवन की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय 'आंतरिक' छात्रों को कक्षा XI व स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10% अंकों में लाभ दिया जाना चाहिए।

(iv) कुलपति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में नामांकन 20% से 5% किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) कोर्ट ने 20-8-89 को हुई अपनी बैठक में तैयबजी समिति की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया तथा सामान्य कोटे में से विश्वविद्यालय कर्मचारियों व पुराने लड़कों के पुत्र व पुत्रियों के लिए क्रमशः 10% व 5% सीटों के आरक्षण के सुझाव के साथ सिफारिशें स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया । कोर्ट ने तैयबजी समिति की सिफारिशों को शैक्षिक परिषद के विचार हेतु भेजने का भी निर्णय किया। मामला विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद के समक्ष विचार हेतु अभी प्रस्तुत किया जाना है।

Achievement of Operation Blackboard

3178. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state what is the latest position regarding achievement of Operation Blackboard and the details of Government Scheme implemented to make available minimum educational equipment to more than 2,59,000 primary schools in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): The Central Government had launched the Scheme of Operation Blackboard in 1987-88 with a view to providing all 529392 primary schools existing as on 30th September, 1986 with minimum essential facilities comprising (i) an additional teacher in single teacher schools; (ii) two reasonably large all weather rooms, with a deep verandah, along with separate toilet facilities for boys and girls; (iii) essential teaching learning material including blackboards, maps, charts, small library, toys and games and some equipment for work experience. Central assistance is provided for Teacher's Salary and Teaching Learning Equipment. The State Governments/UT Administration are responsible for construction of school buildings.

From 1987-88 to 1989-90, 305569 schools have been covered under the programme, for which Rs. 373.32 crores has been sanctioned for appointment of 78492 additional teachers in single teacher schools and for procurement of the essential equipment 57782 school buildings have been taken up for construction.

Employment to incapacitated IPKF Personnel

3179. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 1158 incapacitated personnel of the Indian Peace Keeping Force to Sri Lanka had applied for employment;

(b) if so, whether any efforts are being made by Government to provide them with jobs on priority basis; and

(c) if so, the details thereof and the number of applicants who had been provided with the jobs till the end of June, 1990?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) to (c) The number of IPKF personnel disabled-invalidated is 69.